RAJYA SABHA

Thursday, the 3rd May, 1990/13 Vaisakha, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rise in prices of consumer goods after the Budget

*41. SHRI RAM JETHMALANI: SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: t

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the Financial Express of the 11th April, 1990 captioned "10 per cent Post Budget price rise";

(b) if so, whether it is a fact that the prices of most of the essential consumer goods, especially the prices of vegetable oils, edible oils and pulses have shown an upward trend during the recent past; and

(c) if so what is the extent of price rise as per Government's estimate, what are the reasons therefor and what effective steps are being taken to contain the prices?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI ANIL SHASTRI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The news-item published in 'Financial Express' of 11th April, 1990 gives a misleading caption. The overall increase in WPI during the four weeks ending 14th April, 1990 works out to 1. 6 per cent. The prices of individual commodities mentioned namely edible oils and pulses have gone up by 2. 7 and 5. 4 per cent respectively during this period. The price of Vanaspati (representing vegetable oils) has gone up by 0. 9 per cent. In addition to supply-demand imbalances in respect of individual commodities and the impact of fiscal levies, the period after mid-March is characterised by normal seasonal pressures due to low market arrivals of agricultural produce.

Government has taken several measures to keep the prices under check. These include effective use of the PDS, sizeable import of edible oils, continued import of pulses and staggering of tea exports. At the same time, effective demand is being checked through curbs on growth of liquidity in the economy, close monitoring of budget deficit and intensified action against hoarders and black marketeers.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: महोदय, **(व्यवधान)** महोदय, **(व्यवधान)**

श्री सभापति : उनके लिए महोदय कहना इस वक्त माकूल लगता है। मतलब यह है कि अमरीका से आए हैं, अच्छा असर हुआ है **(व्यवधान)** अब महोदया सोचना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद हम वेलकम करेंगे, उनकी दावत पर चलेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति महोदय, बात यह है कि चेयर का लिंग स्त्रीलिंग है **(व्यवधान)** सभापति महोदय, अब आपकी इजाज़त हो तो मैं मन्त्री जी से प्रश्न पूछता हूं। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार भ्रामक है। लेकिन उन्होंने जो दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों में मूल्यों में 1.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, यह दावा भी भ्रामक मालूम होता है। एक एक वस्तु के दाम का विश्लेषण किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने जो विश्लेषण किया है वह थोक दामों का विश्लेषण है जबकि उपभोक्ता को फुटकर आधार पर सामान खरीदना पड़ता है। अब वनस्पति का ही मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है कि केवल 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बाज़ार तो यह नहीं कहता। बाज़ार में वनस्पति की कीमतों में उछाल आया है और सरकार रोक नहीं पा रही है। दाम बांधो, यह तो डा० लोहिया का बड़ा पुराना नारा था और बड़ा प्रभावी नारा था मगर सरकार दाम बांधने में सफल नहीं हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो 1.6 प्रतिशत का दावा किया गया है, इसका आधार क्या है? क्या यह थोक मूल्यों पर

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Atal Bihari Vajpayee.

आधारित है या इसका कोई अन्य आधार है? दूसरी बात इसी के साथ जुड़ी हुई है। सरकार ने वक्तव्य में कीमतों को कम करने का उल्लेख किया है। जो कदम दामों को कम करने के लिए उठाये गये उनका क्या असर हुआ है और इस समय 1.6 प्रतिशत है वह इससे ज्यादा है या कम है?

श्री अनिल शास्त्री: सभापति जी, मूल्यों का जो हम आधार निकालते हैं वह दो तरह से है एक तो होल-सेल प्राइस इंडेक्स होता है और दूसरा कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। होल-सेल प्राइस इंडेक्स जो है वह वीकली-बेसेज़ पर हमें मिलता है और कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वह दो महीने पर मिलता है। तो हमारे पास जो कन्ज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर प्राइसेज़ अलग-अलग वस्तुओं के हैं वह फरवरी तक के हैं और जो मैंने अपने जवाब में 1.6 प्रतिशत का उल्लेख किया है यह बजट के पेश होने के चार हफ्ते के बाद तक का है, 25 अप्रैल, 1990 तक का है।

श्री सभापति: यह होलसेल का है।

श्री अनिल शास्त्री: यह होलसेल का है। होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से है और हम लोगों ने जो कदम उठाये हैं चाहे वह सीमेंट हो, स्टील हो, चीनी हो इसमें तीन चार बातें सरकार ने की हैं। एक तो यह है कि जो मैनुफैक्चरर्स हैं जैसे स्टील के मसले पर हमारे स्टील मंत्री और उद्योग मंत्री ने सीमेंट के मैनुफैक्चरर्स से बात की है और दूसरा जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इस पर भी इफेक्टिव कदम उठाये जा रहे हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक रहे और जो सामान बाजार में आये उसका वितरण ठीक से हो और कंज्यूमर्स को सामान ठीक दाम पर मिल सके।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, सुनील जी का उत्तर सुनकर...

कई माननीय सदस्य: अनिल जी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आज कुछ गड़बड़ हो रही है...**(व्यवधान)**

श्री माखन लाल फोतेदार: अटल जी, यह तो आपकी ही...**(व्यवधान)** कृपा पर निर्भर सरकार है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: नहीं, मैं कुछ एक मार्मिक बात कहने वाला हूं। जब वे उत्तर दे रहे थे तो मुझे स्वर्गीय शास्त्री जी की बात याद आ रही थी।

श्री सभापति: आवाज एक ही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: जी हां, वही आवाज है, वही कदम है, उत्तर देने का लहजा भी वही है और उत्तर बहुत अच्छे ढंग से देने का प्रयत्न किया है। मगर अब मूल्यों की स्थिति खराब है तो बेचारे शास्त्री जी क्या कर सकते हैं।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने कहा कि हमने मैनुफैक्चरर्स को बुलाकर कीमतें कम करने के बारे में, कीमतें उचित रखने के बारे में बातचीत की है। क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े कारखाने वाले रोजमर्रा के काम में आने वाली अपनी चीजों के दाम जो तय करते हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ कोई संबंध नहीं होता। वे अनाप-शनाप मुनाफा कमाते हैं। उदाहरण के लिए हीरो-होंडा मोटर साइकिल जो 20 हजार रुपये में बिकती है हमने उसके हिसाब-किताब की जांच की, 20 परसेंट उस पर मुनाफा जोड़ा तो वह मोटर साइकिल 12 हजार रुपये से ज्यादा नहीं बिकनी चाहिए। क्या मंत्री महोदय इस बात का पता लगाने का प्रयत्न करेंगे कि जो मैनुफैक्चरर्स हैं, और मैं छोटे-छोटे निर्माताओं की बात नहीं कर रहा हूं, जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, बड़े-बड़े घराने हैं वे कारखानों में निर्मित वस्तुओं पर कितना मुनाफा कमा रहे हैं। क्या उसका कास्ट आफ प्रोडक्शन से कोई संबंध नहीं होना चाहिए? मैंने स्वयं श्री मधु दण्डवते को, जब वे वित्त मंत्री बने थे तो इस संबंध में एक पत्र लिखा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैनुफैक्चर्ड गुड्स की प्राइस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इनका कोई संबंध हो, इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हम यह मांग करते हैं कि पैरिटी होनी चाहिए।

श्री जगेश देसाई: वही तो हमने मांग की है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: ऐग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और मैनुफैक्चर्ड गुड्स के दामों में पैरिटी होनी चाहिए। वह पैरिटी भी नहीं हुई है...**(व्यवधान)**

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी: आप लोग क्यों बात करते हैं क्वेश्चन चल रहा है...**(व्यवधान)**

श्री सभापति: बोलने दिया करें। यह क्या है। लोग हंसते हैं आजकल हमारे हाउस पर।

श्री सीताराम केसरी: हंसने के लिए हाउस है ही।

श्री सभापति: क्या इस पर दूसरे लोग हंसे? अपने लोग हंसे तो ठीक है।

श्री सीताराम केसरी: सब लोग हँसे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: सभापति जी, इस

समय तो हंसने की बात नहीं हो रही है रोने की हो रही है... **(व्यवधान)**

श्री सीताराम केसरी: मगर आपके चेहरे पर मुसकुराहट है, रुदन का कोई चिन्ह नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: केसरी जी, जो आपके पड़ोस में बैठे हैं यह उसका असर है।

श्री सीताराम केसरी: हां, यह ठीक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: श्री जगेश देसाई जी ठीक कह रहे थे कि इस तरह की मांग हुई है कि पैरिटी होनी चाहिए। कारखानों में जो माल बनता है उसकी कीमत का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कोई संबंध होना चाहिए। क्या सरकार ने इस मामले में गहराई से विचार-विमर्श किया है और अगर नहीं किया है तो क्या करेगी, और क्या बड़े-बड़े निर्माताओं से कहेगी कि अपनी चीज़ों के दाम घटायें, मुनाफा थोड़ा कम करें?

श्री अनिल शास्त्री: सभापति जी, माननीय सदस्य जी ने शास्त्री जी का जिक्र किया, तो मैं भी यह कहना चाहूंगा आज सदन में कि मेरा भी यह सौभाग्य है कि मंत्री बनने के बाद पहला सवाल मुझसे सदन के वरिष्ठ नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसका उत्तर देना पड़ रहा है। जहां तक माननीय सदस्य ने जिक्र किया है कि पैरिटी होनी चाहिए, जो मैनुफैक्चरर्ज़ का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है और जिस दाम पर वह बेचते हैं, इसमें वह ज्यादा मुनाफा न कमायें, सरकार पूरी तरह से इस कोशिश में है कि ऐसा न होने पाये।।

बल्कि प्रधान मंत्री जी ने यह कहा भी है कि जहां पर यह देखा जाएगा कि जो मैनुफैक्चरर्ज़ ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं या होर्डर्ज़ माल की होर्डिंग कर रहे हैं, उनका सारा माल सरकार लेकर मार्केट में रिलीज़ करेगी। जहां पर जिन वस्तुओं की जरूरत होगी, जैसे ऐडिबल आयल्ज़ हैं, वहां पर इम्पोर्ट भी किया जाएगा, आयात भी किया जाएगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य की बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जो मैनुफैक्चरिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट है और जिस दाम पर वह अपनी वस्तु बेचते हैं, उसमें पैरिटी होनी चाहिए।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि सरकार इस पर पूरी तरह से गौर कर रही है और पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि ऐसा न होने पाये और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसके आधार पर जो रीज़नेबल मुनाफा है, वह लेकर माल बाजार में लाया जाए।

SHRI SUKOMAL SEN: The point is that the prices are rising all round; particularly after the Budget the prices of all essential commodities have gone up. There are two aspects of it. One is distribution through the public distribution system. Another aspect is to a certain extent the Budget has caused the rise in prices. I would like to know from the honourable Minister whether the Government increases the procurement price of the agricultural produce, whether it is rice or wheat or anything else. While distributing through the. public distribution system, if at that time the issue- price is also increased, then what happens is—you give relief to the peasants by raising the procurement price and that is all right —when the issue price is raised, the entire burden is shifted to the consumers. Government has done the same thing in respect of wheat. I would like to know why the Government has done it. It has put additional burden on the shoulders of the people. Then, when the budget was presented we discussed this question and it was almost the universal opinion—I do not know whether the Government agrees or not—the rise in the prices of petrol and diesel has contributed to the rise in the prices of other commodities. Therefore, there is now a demand that the rise effected in the prices of petrol and diesel should be withdrawn so that the prices of other commodities may stabilise. Will the Government, therefore, agree to withdraw the rise in the prices of petrol and diesel?

SHRI ANIL SHASTRI: As I have already stated in my earlier reply laid on the Table of the House, it is a little misleading to say that the prices have gone up immediately after the Budget. In fact, in the previous year also there had been an increase after the Budget. Of course, last year four weeks after the Budget was presented, the increase in the wholesale price index was 0. 6% and this year it was 1. 6%. Of course, this year there is a greater increase. But then, to say that the price rise is only on account of the Budget is not really true, because

price rise takes place through a combination of factors like lower production; ' at times we have to meet certain export commitments, export commitments have to be met. In the case of tea, of the CTC variety, I would like to inform the honourable Member that we have decided to stagger our exports to the Union of Soviet Socialist Republics.

So it is not really true that the prices have increased because of the Budget which was presented in the month of March. The hon. Member mentioned about the agricultural produce. I would like to state that we have decided to give a higher price to the farmers on agricultural produce simply because we want that the production of foodgrains must increase. Unless we give higher and remunerative prices to the farmers, we cannot ensure that the production goes up. The whole thrust of the Government is that the production should go up.

MR. CHAIRMAN: He has asked why the issue price Was raised.

श्री सीताराम केसरी : माननीय सभापति जी, मैं आपके द्वारा सरकार से यह जानना चाहूंगा जैसा अभी अटल जी ने कहा कि उद्योगपतियों की बेईमानी के कारण जैसा उन्होंने मोटर साइकिल की कीमत का उदाहरण दिया उनकी वजह से कीमतें बढ़ती हैं और 20 प्रतिशत कॉस्ट प्राइस पर जो मुनाफा करते हैं क्या कोई ठोस कदम उनके खिलाफ उठायेंगे जिससे कि कीमत नीचे गिरे और इसके लिए कोई भूमिका बतायेंगे?

दूसरी बात जो उन्होंने यह कहा कि प्रयत्न और प्रयास करूंगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रयत्न या प्रयास की जगह पर कोई ठोस कदम उठाने का फैसला किया है या नहीं जिससे कि कीमत घटे?

श्री अनिल शास्त्री : जैसा मैंने अभी बताया कि मैनुफैक्चरर्ज़ से बात की गई है, हमारे उद्योग मंत्री ने बात की है और सीमेंट का मैं एक उदाहरण दूंगा कि सीमेंट में हम लोगों को लगा कि जो प्राइस बढ़ी थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बहुत ज्यादा थी और हम लोगों ने उद्योगपतियों से बात करके, सीमेंट उत्पादकों से बात करके उनसे कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसके आधार पर ही प्राइस बाजार में लिया जाए होलसेल प्राइस, लेकिन आपको यह भी मैं बताना चाहूंगा कि जो इस समय प्राइस है दाम सीमेंट का पर बैग है वह 80 रुपये हो गया है जबकि अभी कुछ ही दिन पहले करीब 90 रुपये था।

एक माननीय सदस्य : 110 हो गया ...(व्यवधान)

श्री अनिल शास्त्री : 110 तो बहुत पहले था, लेकिन इसके 15 दिन पहले 90 था।...(व्यवधान) 106 बहुत पहले था। पिछले दो हफ्ते पहले 90 था, पिछले हफ्ते 85 था और अब 80 है।

श्री सभापति : अब 80 है।

श्री अनिल शास्त्री : अब 80 है।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहूंगी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जवाब में उन्होंने कहा कि कारखाने का जो उत्पादित सामान है और खेती के उत्पादित सामान जैसे वेजिटेबल आयल, एडिबल आयल इत्यादि बनते हैं या दाल वगैरह तो उसकी कीमतों में कोई सामंजस्य नहीं है और मंत्री जी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वह सामंजस्य बनाया जाए, तो मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि क्या कोई समय-सीमा इन्होंने निर्धारित की है कि कितने दिनों के अन्दर कीमतों पर हम काबू पायेंगे, क्योंकि समय आपके लिए बैठा नहीं रहेगा और कंज्यूमर गुड्ज़ की जो कीमत बढ़ती जा रही है उससे लोगों की बहुत परेशानी बढ़ रही है?

श्री अनिल शास्त्री : जैसा अभी मैंने कहा कि कीमतें कम हुई हैं, सीमेंट का मैंने उदाहरण दिया। चाय का भी दाम कम हुआ है। तो जहां तक समय बताने की बात है मैं समझता हूं कि अगले 6 हफ्ते में हम लोग दाम को, प्राइस को काफी नीचे लाने में सक्षम हो पायेंगे।

श्रीमती कमला सिन्हा : सभापति जी, प्रधान मंत्री जी ने तो एक महीने का समय कहा और मंत्री जी सदन में 6 हफ्ते का वक्तव्य दे रहे हैं?

श्री सभापति : थोड़ा ही फर्क है।

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि यह देखेंगे कि रोजमर्रा की चीजों का वितरण ठीक ढंग से हो और वे ठीक दाम पर मिलें।

मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि रोजमर्रा की चीज़ों को विक्रय करने वाले दुकानदार अपने वहां स्टाक लिस्ट और रेट लिस्ट आवश्यक रूप से लगाएं ताकि

ग्राहकों को पता लग सके कि अमुक दुकानदार के पास किस चीज का कितना स्टाक है और उसकी वास्तविक कीमत क्या है ताकि वह अनावश्यक मुनाफा न ले सके और क्या इस हेतु केन्द्रीय सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को कुछ निर्देशन दिया जा रहा है?

श्री अनिल शास्त्री : महोदय राज्य सरकारों से इस के बारे में बात हुई है और माननीय सदस्य जी का सुझाव बड़ा अच्छा है। जो रेट लिस्ट वगैरा की सूची लगाने की बात है, इस पर मैं जरूर बात करूंगा, लेकिन हम लोगों ने राज्य सरकारों से बात की है कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसे इफेक्टिव बनाया जाये। उन के कुछ सुझाव भी आए हैं और माननीय सदस्य का भी यह सुझाव आया है। हम लोग इस बारे में बात करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो यह प्रणाली है, इस को हम पूरी तरह से ठीक और सक्षम करेंगे।

SHRI N. E. BALARAM: Sir, the prices of certain consumer goods are already on the rise, and the Minister in his reply was telling that one of the reasons was that there is shortage in production. I think, it is not factually correct because, according to the statistics published by the Government itself, the production of cement, sugar, edible oil, etc. was increasing, and there is no weakness on the supply side. What is happening according to me is • that some of the major industrial houses are not releasing the stocks and they are creating a sort of artificial scarcity in the market. I would like to know what steps the Government are going to take in this matter. Are they thinking of dehoarding the goods? Otherwise, the price will go up. For instance, what is the state of affairs of sugar? Sugar production has reached the peak this time. But in the market, the price of sugar has gone up. Yesterday, it was about Rs. 11 per kg. It is not due to shortage of goods but what is happening in the market. So, I would like to know from the Minister whether he is thinking of dehoarding the stocks and releasing the stocks.

SHRI ANIL SHASTRI: Well, the hon. Member has stated that there has not been any scarcity on account of shortage of production. Sir, it is not so. I have some figures which I would like to place before you, Sir. The price rise in the case of sugar, since sugar was mentioned, during the year was mainly due to decline in the sugar production to the level of 87 lakh tonnes during the sugar year October to September, 1988-89—the sugar year is from October to September—from 92 lakh tonnes in the sugar year 1987-88. So, in the previous year, the production was 92 lakh tonnes which has come down to 87 lakh tonnes which is about 5 lakh tonne less production this year. The rising sugar consumption, inflationary expectation generated by speculative activities, and low level of closing stocks are responsible also for pressure on sugar prices. Now, the other question is regarding the steps that we are taking. To check the market price, the Government has released larger quantities of sugar, both of free sale and levy, and provided incentives for higher

producing during off season. The total release of sugar during the financial year 1988-89 was, higher at 105. 09 lakh tonnes compared with 99. 74 lakh tonnes in the previous" year. So, we have released a higher quantity of sugar. A quantity of 2. 4 lakh tonnes of sugar was also imported during the year to augment domestic supplies. Now, I would also like to inform the hon. Member that during 1989-90 sugar season, the total production of sugar during the first six months has been 81. 69 lakh tonnes which is substantially higher than the production of 74. 80 lakh tonnes in the first six months of the previous sugar year. For the month of April, 1990, a quota of 9. 32 lakh tonnes has been released consisting of 6 lakh tonnes of free sale and 3. 32 lakh tonnes of levy sugar.

And out of 2. 4 lakh tonnes of import, which I just mentioned, 0. 75 lakh tonnes has been released by the end of April 1990. This is higher than the quantity released in March 1990. So, the prices

have gone up in the case of sugar, edible oils, cement on account of.............

MR. CHAIRMAN: Are you trying to bring them down?

SHRI ANIL SHASTRI: Yes, Sir.

MR. CHAIRMAN: Question No. 42

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति महोदय, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा निवेदन है कि इस पर हाफ-एन-ऑवर डिस्कशन होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, बढ़ती हुई कीमतों से आज आम आदमी चिंतित है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

SHRI SURESH KALMADI: We have already given notice for a half-an-hour discussion.

MR. CHAIRMAN: We are discussing it

श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर : महोदय,*

श्री सभापति : आप बैठ जाइए। यह क्वैश्चन ऑवर है। क्या मजाक है। ...(**व्यवधान**)...

Please sit down. Nothing will go on record. I have called Question No. 42. It has already been decided that there will be a short duration discussion.

Yes, Question No. 42.

Suggestions of FICCI for setting up integrated steel plants

*42. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL. Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry has suggested the setting up of integrated steel plants in the private and joint sectors and also for increasing the capacity of mini steel plant in the private sector; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF COMMERCE AND TOURISM (SHRI ARUN KUMAR NEHRU): (a) No Sir.

(b) Does Not arise.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: चैयरमेन महोदय, कोई सवाल करने से पहले मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री सभापति: वह तो है हमेशा।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: सरकार के इन मंत्रियों से हमें खतरा है। इस सरकार के जो मंत्री हैं, उनसे हमें खतरा है।

श्री सभापति: किनसे? इनसे?

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: महोदय, मैं बताता हूं, मेरी बात सुनिए। इन मंत्रियों से हमें खतरा है। अरुण नेहरू जी तो स्टील मंत्री भी नहीं हैं। यह तो बेचारे सबस्टीट्यूट कर रहे हैं। परसों 30 तारीख को, सेशन के पहले दिन जो फर्स्ट क्वैश्चन था, वह एअर-बस के बारे में था।

श्री सभापति: तो कहां एअर-बस और कहां स्टील?

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: आप जरा मेरी बात सुनेंगे, तो फिर प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। आप मेरी बात सुनेंगे तो प्रोटेक्शन हो जाएगी।

श्री सभापति: जल्दी-जल्दी कीजिए। यह क्वैश्चन-ऑवर है। इसमें छोटे-मोटे सवाल होने चाहिएं।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: मंत्री महोदय ने एक क्वैश्चन के जवाब में कहा— "The matter is under consideration." That was the answer. कल तीसरे क्वैश्चन के जवाब में...

श्री सभापति: कल का सवाल नहीं, आप इस सवाल पर सप्लीमेंटरी कीजिए, प्लीज।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: जब कहा गया कश्मीर के बारे में, कि कोई कमेटी बनाई है? तो कह दिया कि नहीं बनाई। जब हमारे मेम्बर ने बताया कि कमेटी बनी है तो उसके बारे में जवाब देना शुरू कर दिया।

श्री सभापति: आप अपने सवाल पर ही सप्लीमेंटरी कीजिए।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: आज मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है—"नो सर"। मैंने पूछा था कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इन्डस्ट्री के प्रेसिडेंट की तरफ से कोई सुझाव आया है?

श्री सभापति: वह कहते हैं कि नहीं आया।

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल: मेरे पास यह अखबार की कटिंग है, 18 मार्च की। बहुत लंबा-चौड़ा स्टेटमेंट

*Not recorded.